संख्या- 17 /2019 / 3496 /छिहत्तर-1-19-1 घोषणा/2018

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त, ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 27 दिसम्बर, 2019

विषयः राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद- उन्नाव के 19 मजरों में कुल 19 आर0ओ0 आधारित मिनी पाइप पेयजल योजना के निर्माण (लागत ₹ 181.12 लाख) की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-13)

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम के पत्र संख्या-355 /2042-0063 (लखनऊ) /मा0 मुख्यमंत्री घोषणा/19, दिनांक 26.10.2019 तथा अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के पत्र संख्या-1268 /डब्लू-20/ 2019-20, दिनांक 02 दिसम्बर, 2019 के माध्यम से राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड-सरोसी के ग्राम पंचायत सथरा के मजरा- मोददीनपुर, चन्दनखेडा, करीमाबाद, कोटिरहिया, विकास खण्ड सरोसी के ग्राम पंचायत ऐरा भदियार के मजरा-भदियार, कुशलीखेडा, गिरिवर खेडा, दीवान खेडा , विकास खण्ड सरोसी के ग्राम पंचायत पतारी के मजरा- पटकापुर, कुबेरखेडा, प्यारेपुर विकास खण्ड सि0 कर्ण के ग्राम पंचायत कटहा दलनरायनपुर के मजरा- हैबतपुर, चेतखेडा, बाबा खेडा, खन्जी खेडा, दुर्जन खेडा एवं शंकर पुरवा अर्थात कुल 19 पुरवों में 19 आर0ओ0 आधारित मिनी पाइप पेयजल योजना के निर्माण हेतु कुल अनुमानित लागत ₹181.12 लाख के प्रस्ताव पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्य ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-13 में प्राविधानित धनराशि में से अवमुक्त करते हुए आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित विवरण/ शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उपर्युक्तानुसार जनपद-उन्नाव के 02 विकास खण्डों के कुल 19 मजरों में आर0ओ0 आधारित मिनी पाइप पेयजल योजना का निर्माण /क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम को ₹ 181.12 लाख की धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय स्वीकृति की सीमा तक सीमित होगा।
3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि की स्वीकृति नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना / योजना के अन्तर्गत अनुमोदित कार्ययोजना में सम्मिलित है।
4. प्रश्नगत कार्य के लिए नियमानुसार 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजना / कार्य के विस्तृत आगणन का कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। तदोपरान्त धनराशि आहरित की जायेगी।
6. जनपद-उन्नाव के विकास खण्ड, सि0 सरोसी एवं सि0 कर्ण की विभिन्न ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत कुल 19 मजरों की मिनी आर0ओ0 आधारित मिनी पाइप पेयजल योजना की लोकेशन का सुस्पष्ट निर्धारण कर इस पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। उक्त स्वीकृत पेयजल योजना के निर्माण में होने वाली सम्भावित डुप्लीकेसी को रोकने के लिए पूर्णतया प्रमाणित व्यवस्था का निर्धारण करते हुए इसे सक्षम स्तर (मुख्य अभियन्ता) से प्रमाणित कराने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।
7. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि आहरित कर डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार हो आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

8. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री / उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। इस सन्दर्भ में अधिकृत थर्ड पार्टी निरीक्षण कर्ता को भी अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जायेगा।
9. परिसम्पत्ति के सृजन के उपरान्त इसके रखरखाव हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत को हस्तगत कर दिया जायेगा।
10. स्वीकृत परियोजना/कार्य में द्विरावृति से बचने के लिए कार्य के प्रारम्भ, प्रगति के विभिन्न स्तरों के मध्य एवं कार्य की समाप्ति पर वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
11. निर्माण कार्यो को निर्धारित विशिष्टियों / मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित अवधि में पूर्ण किया जायेगा तथा कराये गये कार्यो का अलग से लेखा-जोखा रखा जायेगा । अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
12. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग /महालेखाकार इलाहाबाद को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
13. नियमानुसार यथावश्यक समस्त वैधानिक अनापतियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ् किया जायेगा।
14. राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के दिशा-निर्देशों / मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. योजना के अन्तर्गत होने वाले कार्यो की गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा एक समिति का गठन कर उक्त दायित्व का निर्वहन किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यक के अनुदान संख्या-13 के लेखाशीर्षक 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय -01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति- 05- राज्य ग्रामीण पेयजल योजना-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/ दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्रशासकीय विभाग को प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्याः 17 /2019/3496(1)/छिहत्तर-1-19-01 घोषणा/2018, तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, जल शक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उ0प्र0।
3. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय , उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
8. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।